www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 8 मार्च 2019

दैनिक जागरण

ऊंची छलांग लगाने के लिए पहले कुछ कदम पीछे हटना पड़ता है

सरकार के काम की गति

केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की पुरानी प्रक्रिया बहाल करने के लिए अध्यादेश लाने का जो फैसला किया वह इसलिए जरूरी था, क्योंकि न्यायपालिका की ओर से तय की गई शिक्षकों की नियुक्ति की नई प्रक्रिया का ठीकरा मोदी सरकार पर फोड़ा जा रहा था और दूसरे आम चुनाव के पहले कोई भी सरकार आरक्षित तबके को नाराज करने का खतरा मोल नहीं ले सकती थी। समझना कठिन है कि न्यायपालिका ने ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा की जिससे सरकार को उसके फैसले को पलटने के लिए बाध्य होना पड़ा? इस सवाल पर इसलिए गौर किया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षकों की नियुक्ति की नई प्रक्रिया एक तरह से आरक्षण को खारिज करने का काम कर रही थी और वह भी तब जब विश्वविद्यालयों में आरक्षित तबकों के शिक्षक तय संख्या से कहीं अधिक कम थे। आखिर विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नई प्रक्रिया को किस आधार पर न्यायसंगत और सामाजिक न्याय के अनुरूप मान लिया गया? न्याय होना ही नहीं चाहिए, वह होते हुए दिखना भी चाहिए। निःसंदेह यह समझ आता है कि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती की पुरानी प्रक्रिया को बहाल करने के लिए अध्यादेश लाना सरकार की मजबूरी बन गई थी, लेकिन गत दिवस कैबिनेट में जो अन्य अनेक फैसले लिए गए उनमें से कई एक ऐसे हैं जिनका उद्देश्य यही अधिक लगता है कि सरकार अपने कार्यकाल के आखिर वक्त में तेजी से काम करती हुई दिखना चाहती है। शायद इसीलिए देश में 50 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का फैसला लेने के साथ ही बिजली क्षेत्र में 31 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो परियोजना के चौथे चरण को स्वीकृति देने के साथ चीनी उद्योग और टेक्सटाइल क्षेत्र के निर्यातकों को राहत देने के कदम उठाए गए। इन सबके अतिरिक्त कुछ अन्य फैसले भी लिए गए।

कैबिनेट के ताजा फैसलों के साथ इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि बीते कुछ समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न योजनाओं-परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करते दिख रहे हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं। इसलिए और भी नहीं, क्योंकि विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास के साथ उद्घाटन भी किए जा रहे हैं। ये उद्घाटन यही बताते हैं कि सरकार ने काम करके दिखाया है। अपने कामों का प्रचार करना हर सरकार का अधिकार है। इसी तरह आम चुनाव में उतरने के पहले जनता को यह संदेश देना भी सरकार का अधिकार है कि वह तेजी से काम करने वाली सरकार है। हर सरकार ऐसा ही करती आई है, लेकिन अच्छा होता कि मोदी सरकार ने पहले दिन ही यह तय कर लिया होता कि अगले पांच साल उसे कौन से काम प्राथमिकता के आधार पर करने हैं। अगर ऐसा किया गया होता तो शायद आज उसे कई काम आखिरी समय में करते हुए नहीं दिखना पड़ता। इससे इन्कार नहीं कि इस सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में तमाम काम किए हैं और वे जमीन पर दिख भी रहे हैं, लेकिन शायद प्राथमिकता ढंग से तय नहीं की गई और इसी कारण नई शिक्षा नीति अब तक नहीं आ सकी। ऐसे ही कुछ और काम हैं जो लंबित ही दिख रहे हैं।

संकल्प से मिलेगा लक्ष्य

झारखंड को खुले में शौच से वास्तविक रूप में मुक्त कराने को हर स्तर पर संकल्प लेने का संदेश दे रहा कोल्हान। प्राकृतिक संपदा की दृष्टि से काफी समृद्ध एवं सियासी रूप से अति जागरूक इस क्षेत्र के लोगों में शौचालयों के इस्तेमाल को लेकर रुख ठंडा नजर आ रहा है। एक मोटे आकलन के अनुसार इलाके में अब भी महज 40 फीसद लोग ही शौचालय का इस्तेमाल करते हैं। यह तो एक बानगी है। पूरे राज्य के ग्रामीण इलाकों में कमोबेश ऐसी ही तस्वीर दिखती है। कहीं आधे-अधूरे तरीके से बनाए गए शौचालयों के दर्शन होते हैं। कहीं पानी की आपूर्ति गड़बड़ तो कहीं जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं। जहां सबकुछ ठीकठाक है भी तो समस्या यह है कि शौच के लिए लोग घर से बाहर जाने की आदत छोड़ नहीं पा रहे। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, क्योंकि घर-घर शौचालय निर्माण को लेकर चलाए जा रहे नेक अभियान के साथ खुले मन एवं मजबूत संकल्प से साथ जुड़ाव की हर स्तर पर कहीं न कहीं कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए हर स्तर पर संकल्प लेना होगा। निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करनी होगी। देखना होगा कि शौचालयों के नियमित इस्तेमाल की आदत बनी रहे। यह आकलन सबसे जरूरी है कि आखिरकार क्यों लोग अब भी खुले में शौच करने जाने को प्राथमिकता दे रहे। कारणों की पड़ताल के बाद लोगों की आदत बदलने के लिए मुहिम चलानी होगी। घर-घर जाकर बताना होगा कि शौच के परंपरागत तौर-तरीकों को क्यों छोड़ना जरूरी है। इसके फायदे भी बताने होंगे। इसे लेकर परस्पर संवाद करना होगा। खुले में शौच वाले स्थानों की निगरानी के साथ यह देखना होगा कि स्वच्छता दूत अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाते रहें। यह स्वच्छता दूत ही हैं जो ग्रामीणों को शौचालय बनाने एवं उसका इस्तेमाल करने के लिए भावनात्मक रूप से जोड़ सकते हैं। इसके लिए हर परिवार को बताना होगा कि शौचालय निर्माण एवं इस्तेमाल से परिवार में प्रेम बढ़ेगा, बच्चों की सही तरीके से देखभाल होगी, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा और परिजनों को सुरक्षा मिलेगी। यह भाव बनने लगेगा तो अपने आप गंदगी के प्रति घृणा पैदा होगी जो इस अभियान की सफलता का असली कारक है।

बालाकोट के बाद की चुनौतियां

सी उदयभास्कर

वायुसेना ही नहीं, बल्कि सेना, नौसेना के अलावा अर्धसैनिक बल और जम्मू-कश्मीर पुलिस को भी अत्याधुनिक हथियारों और आधुनिकीकरण की तत्काल आवश्यकता है

भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर जैश-ए-मुहम्मद के बालाकोट स्थित आतंकी ठिकानों पर हवाई हमला किया। अफसोस की बात है कि 26 फरवरी को हुई यह कार्रवाई अनावश्यक राजनीतिक विवादों में फंस गई। मामला इतना खिंच गया कि वायु सेना प्रमुख बीएस धनोआ को प्रेस कांफ्रेंस बुलाकर कहना पड़ा कि बालाकोट ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा। हालांकि सोशल मीडिया में शुरुआती तौर पर किया जा रहा दावा सही नहीं साबित हुआ कि इस हमले में करीब 300 आतंकी मारे गए। देश में फर्जी खबरों की बीमारी हाल के वर्षों में एक महामारी के रूप में उभरी है। इसने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसलों को भी नहीं बख्शा। आगामी चुनावों में फायदा उठाने के लिए तथ्यों को सुविधाजनक रूप से तोड़-मरोड़कर तैयार की गई चाशनी असल में घरेलू विमर्श का जायका बिगाड़ रही है। ऐसे परिदृश्य में पुलवामा आतंकी हमले और उसके बाद के घटनाक्रम का निष्पक्ष विश्लेषण आवश्यक है। सीआरपीएफ के काफिले पर 14 फरवरी को आतंकी हमला हुआ। इसके जवाब में 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में हवाई हमला किया। उसके अगले ही दिन पाकिस्तानी कार्रवाई में हमारा एक मिग-21 पाक सीमा में जा गिरा और विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तानी फौज ने बंधक बना लिया। एक मार्च को पाकिस्तान ने उन्हें भारत को सौंप दिया। यह 1990 के दशक से भारत पर थोपे गए छद्म युद्ध के लंबे पड़ाव की एक परिणति रही जब कश्मीर घाटी में मजहबी चरमपंथ की पहली लहर में कश्मीरी पंडितों को वहां से बेदखल कर दिया गया था।

पुलवामा-बालाकोट-अभिनंदन घटनाक्रम में कई परतें जुड़ी हुई हैं जिनके राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से गंभीर निहितार्थ हैं। विशेषकर ऐसे वक्त में जब भारत जिहादी आतंक की जटिल चुनौती से जूझने की दिशा में अपनी रणनीति की समीक्षा कर उसे दुरुस्त करने की दिशा में बढ़ रहा है। आतंक की यह विषबेल 2001 में संसद पर हुए आतंकी हमले के बाद से और जहरीली होती गई है। मुंबई आतंकी हमलों में इसने अपना फन फिर से उठाया और अब पुलवामा में इसका दुस्साहस फिर से जाहिर हुआ। इसका तात्कालिक नतीजा यही निकलता है कि जम्मू-कश्मीर में आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर हालात तल्ख हो गए हैं। वहां लश्करे तैयबा के दो आतंकियों के खिलाफ एक मुठभेड़ 56 घंटे तक चली। इसमें जो दो आतंकी मारे गए उनमें से एक की पहचान पाकिस्तानी नागरिक के तौर पर भी हुई, लेकिन इसमें भारत को पांच सुरक्षाकर्मी गंवाने पड़े। इनमें तीन सीआरपीएफ और दो जम्मू-कश्मीर पुलिस के जवान थे। 27 फरवरी से 2 मार्च के बीच चार दिनों के दौरान संघर्षविराम उल्लंघन के 43 मामले सामने आए। सुरक्षा परिदृश्य के समक्ष उत्पन्न यह चुनौती दर्शाती है कि बालाकोट हमले के तुरंत बाद सीमापार से घुसपैठ के मामलों में कोई कमी नहीं आई। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि बालाकोट हमले के प्रभाव, दुश्मन से भिड़ंत में मिग-21 विमान को गंवाने और पायलट की वापसी को किस नजरिये से देखा जाए और भविष्य में इसके क्या आसार दिखते हैं जब भारत में लोकसभा चुनाव दस्तक देने जा रहे हैं।

अवधेश राजपूत

बालाकोट का अपना प्रतीकात्मक महत्व है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के शासन में भारत आतंक विरोधी अभियान में वायुसेना का भी इस्तेमाल कर सकता है। इससे यह भी साफ हो गया है कि ऐसी घटनाओं से सैन्य तनाव भी स्वाभाविक रूप से चरम पर पहुंच सकता है। बालाकोट हमले के कुछ दिन बाद यह बात भी सामने आई कि भारतीय लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान के भीतर तक घुसने के बजाय नियंत्रण रेखा पर भारतीय सीमा से ही हमले को अंजाम दिया। यह इसका संकेत है कि अपनी वायु शक्ति के इस्तेमाल में भारत दूरदर्शिता और एहतियात के साथ संयम का भी परिचय देगा। बालाकोट हमले से दुश्मन को कितना नुकसान पहुंचा, इस पर अभी बहस जारी है। मिसाल के तौर पर अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने भी कुछ संदेह जाहिर किए हैं, परंतु इसका सामरिक संदेश यही है कि पाकिस्तान के भीतर आतंकी ढांचों को ध्वस्त करने के लिए भारत ने स्वयं द्वारा खींची गई 'लक्ष्मण रेखा' को लांघा है। बालाकोट हवाई हमले का सबसे बड़ा संदेश यही है। दिल्ली ने दर्शा दिया है कि वह किसी भी तरह के संघर्ष की स्थिति में अपनी वायुसेना के इस्तेमाल से हिचक नहीं दिखाएगी। इसका उपयोग किस तरह करना है, यह परिस्थिति और अभियान की प्रकृति के हिसाब से तय किया जाएगा। भारतीय हमले के बाद पाकिस्तानी कार्रवाई पर कोई हैरानी नहीं हुई।

पाकिस्तानी वायु सेना ने अगले दिन ही जम्मू-कश्मीर में भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने का दुस्साहस किया। इसमें भारत को एक मिग-21 विमान गंवाना पड़ा और उसमें सवार पायलट अभिनंदन को पाकिस्तान ने बंधक बना लिया। यह घटनाक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। यह प्रशंसनीय है कि 1960 के दशक का बना पुराना मिग-21 एफ-16 जैसे अत्याधुनिक विमान से लोहा ले सकता है, लेकिन यह भारतीय वायु सेना के पास अत्याधुनिक उपकरणों की भारी कमी की त्रासद स्थिति की ओर भी इशारा करता है। वायुसेना लड़ाकू विमानों की भारी कमी से जूझ रही है। अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में उसे 126 विमानों की जरूरत थी जो अब बढ़कर 200 का आंकड़ा पार कर चुकी है। अफसोस की बात यह है कि वायुसेना के बेड़े में विमानों का शामिल होना अभी भी शेष है। केवल वायुसेना ही पिछड़ी हुई नहीं है। सेना और नौसेना के अलावा अर्धसैनिक बल और जम्मू-कश्मीर पुलिस को भी अत्याधुनिक हथियारों और आधुनिकीकरण की तत्काल जरूरत है। राफेल पर हो रही सियासी धींगामुश्ती बेहद दुखद है। यह यही दर्शाती है कि घरेलू राजनीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कैसे समझौते किए जाते हैं।

बालाकोट हमले की आखिरी कड़ी विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान की सकुशल स्वदेश वापसी से जुड़ी हुई है। इस मुद्दे पर पूरे देश में भावनाओं का ज्वार उमड़ आया। अगर राष्ट्र की चेतना के लिए पुलवामा हमला 'निर्भया' मामले के माफिक था तो यह बहादुर पायलट अद्भुत शौर्य का प्रतीक बना। इन उमड़ती भावनाओं के दुखद पहलुओं से जुड़े वाकये भी देखने को मिले। जैसे कर्नाटक में एक प्राध्यापक को एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने घुटनों के बल झुककर माफी मांगने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि उसकी एक पोस्ट उन्हें भारत विरोधी लगी थी।

भारतीय राष्ट्रवाद अब दूसरों पर जबरन लादी जाने वाली भावना बन गई है जिसका खाका दक्षिणपंथ से जुड़े शरारती तत्वों द्वारा खींचा जा रहा है। निश्चित रूप से ये वैसे लोकतांत्रिक मूल्य नहीं जिनसे भारत की पहचान जुड़ी है या जिनके लिए सैनिक अपनी जान की बाजी लगा देता है। पुलवामा-बालाकोट-अभिनंदन से जुड़े घटनाचक्र में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कई संदेश निहित हैं। उनकी समुचित समीक्षा कर उनके दीर्घावधिक संभावित परिणामों के अनुकूल रणनीति बनाने की दरकार है। बालाकोट उस छद्म युद्ध के खिलाफ एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकता है जिससे भारत 1990 के दशक से ही जूझ रहा है।

(लेखक सामरिक मामलों के विशेषज्ञ और सोसायटी फॉर पॉलिसी स्टडीज के निदेशक हैं)

response@jagran.com

वक्त की मांग है लैंगिक समानता

डॉ. मोनिका शर्मा

हम सब यह ध्यान रखें कि महिलाओं के प्रति भेदभाव के बुनियादी कारण हमारे सामाजिक ढांचे में ही मौजूद हैं

महिलाएं समाज और परिवार की धुरी हैं, लेकिन उनके साथ दोयम दर्जे के व्यवहार की समस्या अभी भी बरकरार है। समानता का इंसानी हक आज भी आधी आबादी को सही तरह हासिल नहीं हुआ है। भारत ही नहीं दुनियाभर में स्त्रियां अपनी पहचान बनाने को जूझ रही हैं। उनके इस संघर्ष में सबसे बड़ी बाधा लैंगिंक असमानता है। पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद असमानता की खाई आधी आबादी के लिए दंश बनी हुई है। गैर बराबरी की सोच और व्यवहार से आधी आबादी को घर से लेकर दफ्तर तक हर जगह दो-चार होना पड़ता है। एक अध्ययन के अनुसार भारत ही नहीं दुनियाभर में बढ़ती आर्थिक असमानता से सबसे ज्यादा लड़कियां और महिलाएं प्रभावित हो रही हैं। शायद यही वजह रही कि इस साल महिला दिवस के लिए यूएन की थीम भी इसी विषय को संबोधित है- 'थिंक इक्वल, बिल्ड स्मार्ट, इनोवेट फॉर चेंज।' इस थीम का उद्देश्य ऐसे प्रयासों को बल देना है जिनसे लैंगिक समानता आए, महिलाएं सशक्त और आत्मनिर्भर बनें। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से जुड़े क्षेत्रों में स्त्रियों की भागीदारी बढ़ाने का विचार लिए इस थीम का लक्ष्य कामकाजी आबादी में महिलाओं की हिस्सेदारी में इजाफा करना है ताकि यूएन द्वारा 2030 तक तय किया गया लक्ष्य प्लेनेट 50-50 हासिल किया जा सके। प्लेनेट 50-50 का मकसद है एक ऐसी दुनिया बनाना जिसमें पुरुष और महिलाएं बराबर का हक रखें। इसका एक अन्य उद्देश्य लैंगिंक समानता स्थापित करना भी है। हालांकि इस बदलाव के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जाने आवश्यक हैं, लेकिन लैंगिक समानता की बुनियाद बनाने के लिए समाज और परिवार की भूमिका सबसे अहम है।

तमाम तरक्की के बावजूद परंपरागत रूप से हमारे समाज में महिलाओं को अभी भी कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता है और उनकी भागीदारी को कम करके आंका जाता है। नतीजतन घर और दफ्तर, दोनों जगहों पर महिलाएं उपेक्षा, शोषण, अपमान और भेदभाव को झेलती हैं। महिलाओं के प्रति भेदभाव का यह व्यवहार दुनिया के हर हिस्से में मौजूद है-कहीं कम तो कहीं ज्यादा। विश्व आर्थिक मंच की लैंगिक अंतराल रिपोर्ट-2018 में 144 देशों की सूची में भारत 108वें पायदान पर पाया गया। यह मंच स्त्री-पुरुष असमानता को चार मुख्य मानकों आर्थिक अवसर, राजनीतिक सशक्तीकरण, शैक्षणिक उपलब्धियां और स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता के आधार पर तय करता है। यही वे मानक हैं जो किसी भी देश की महिलाओं का स्वतंत्र अस्तित्व गढ़ने और उसे कायम रखने का आधार बनते हैं और उन्हें स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाते हैं। इस

रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर लैंगिक अंतराल को 68 फीसदी तक कम किया गया है। इस रिपोर्ट में भारत में कन्या भ्रूण हत्या, महिला साक्षरता और मातृ मृत्यु दर जैसे कारणों को महिलाओं के सशक्तीकरण और समानता से जुड़े चिंतनीय पहलुओं की फेहरिस्त में रखा गया है। विश्व आर्थिक मंच के इस अध्ययन में चेतावनी देते हुए कहा गया है कि जिस हिसाब से असमानता दूर करने के लिए प्रयास हो रहे हैं उन्हें देखते हुए पूरी दुनिया में सभी क्षेत्रों में महिला-पुरुष असमानता को अगले 108 साल तक दूर नहीं किया जा सकता। चूंकि कार्यस्थलों पर गैर-बराबरी की खाई बहुत ज्यादा गहरी है इसलिए उसे पाटने में 200 वर्ष तक लग सकते हैं। यह परिदृश्य वाकई चिंतनीय है। एक कटु सच यह भी है कि महिलाओं के प्रति भेदभाव और शोषण के बुनियादी कारण हमारे सामाजिक ढांचे में ही मौजूद हैं। इनका निवारण सिर्फ आर्थिक आत्मनिर्भरता या प्रशासनिक कार्ययोजनाओं के माध्यम से नहीं खोजा जा सकता।

भारत में जिस तरह का पारंपरिक सामाजिक ढांचा है उसमें केवल सरकारी योजनाएं और कानून महिलाओं को सशक्त नहीं बना सकते। असमानता के दंश से मुक्ति पाने के लिए समाज की सोच में भी बदलाव की जरूरत है। इस जरूरत की पूर्ति इसलिए की जानी चाहिए, क्योंकि महिलाओं का उत्थान और उनका सशक्तीकरण परिवार और समाज की बेहतरी में ही सहायक बनेगा। देश के सर्वांगीण विकास के लिए भी हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ना जरूरी है। हमारे देश में सबसे ज्यादा बदलाव की दरकार समाज में मौजूद परंपराओं और रूढ़ियों को लेकर है। बेटे और बेटी में किए जाने वाले भेद की मानसिकता के चलते आज भी दूर-दराज के गांवों में बेटियों की शिक्षा और उनके स्वास्थ्य को महत्व नहीं दिया जाता। आज भी हमारे परिवारों में महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा को व्यवस्थागत समर्थन मिलता है। महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के मोर्चे पर तो अनगिनत चिंताएं हैं ही, घरेलू हिंसा, दहेज, कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह जैसे दंश भी बेटियों के जीवन के दुश्मन बने हुए हैं। सबसे खराब बात यह है कि सार्वजनिक स्थलों में महिलाएं खुद को सुरक्षित नहीं पातीं। यह स्थिति सभ्य समाज के लिए कलंक की तरह है। वे कैसे हर जगह स्वयं को सुरक्षित महसूस करें, इसकी चिंता हर किसी को करनी चाहिए। यह चिंता करना केवल सरकार का काम नहीं।

अनगिनत विरोधाभासों से जूझते हुए महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। सशक्त बनने के मोर्चे पर आधी आबादी ने साबित किया है कि वे स्वयंसिद्धा हैं। आज जब वे जीवन के हर क्षेत्र में खुद को साबित कर रही हैं तब यह देखना पीड़ादायी है कि तमाम क्षमता और योग्यता के बावजूद उन्हें कम करके आंकने की सोच समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। लैंगिक समानता भारतीय संविधान के मूल तत्वों में समाहित है। भेदभाव विरोधी तमाम कानूनी प्रावधान भी मौजूद हैं, फिर भी महिलाएं दोयम दर्जे का व्यवहार झेलने को मजबूर हैं।

आज की उदारीकृत व्यवस्था में महिलाएं श्रम शक्ति का एक बड़ा हिस्सा जरूर हैं, लेकिन वे उपेक्षा और शोषण की शिकार भी बन रही हैं। राजनीतिक भागीदारी से लेकर हर क्षेत्र की वर्कफोर्स में उनके बढ़ते दखल के बावजूद शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक मोर्चे पर पीछे रह जाने का कारण उनका महिला होना ही है। लैंगिक असमानता के चलते ही अस्मिता और सामाजिक सम्मान से जुड़े सरोकार के संघर्ष में महिलाएं आज भी खुद अकेले पाती हैं। एक लोकतांत्रिक देश की नागरिक होने के नाते सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए लैंगिक असमानता को दूर करना आवश्यक है। बराबरी का यह भाव स्त्री अस्मिता ही नहीं मानवीय मूल्यों से भी जुड़ा है, जो हमारी सामाजिक-पारिवारिक व्यवस्था की दशा और दिशा तय करता है। कुल मिलाकर आज यह समझना कहीं अधिक जरूरी है कि समाज और परिवार को लैंगिक समानता की बुनियाद बनना चाहिए।

response@jagran.com

ऊर्जा

अहंकार

अहंकार की छाया में किसी भी सृजनात्मक कार्य का हो पाना कदापि संभव नहीं है, क्योंकि अहंकार रूपी विष हमारी प्राकृतिक ऊर्जा को नष्ट करता रहता है। क्रोध, घृणा और नफरत के पनपने में इसी की अहम भूमिका होती है। अहंकार को रोकने में यदि हम सफल हो जाते हैं तो उस स्थिति में प्राकृतिक ऊर्जा हमारे मस्तिष्क में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहेगी जो हर प्रकार का सृजनात्मक कार्य करने के लिए हमें प्रेरित करती रहेगी। अहंकार क्रोध का मुख्य जन्मदाता है। क्रोध जितने अधिक समय तक मस्तिष्क में रहेगा, उतनी ही अधिक प्राकृतिक ऊर्जा इसे निष्प्रभावी करने में खर्च होती रहेगी। इसके बाद भी यदि क्रोध विद्यमान रहता है तो उस स्थिति का सामना करने के लिए मस्तिष्क रक्त से ऊर्जा प्राप्त करने का प्रयास करता है। यह वह स्थिति होती है, जब रक्त मस्तिष्क की ओर तेजी से खिंचता है। कई बार ऐसा होने पर एक स्थिति ऐसी भी आ जाती है जब हल्के से क्रोध पर भी रक्त इसी प्रकार से मस्तिष्क की ओर तेजी से खिंचने लगता है, क्योंकि ऐसा होते रहने से यह मस्तिष्क के स्वभाव में आ जाता है। वास्तव में हाई ब्लड प्रेशर यही होता है जो एक बार जन्म ले लेता है, तब यह पीछा नहीं छोड़ता है।

अहंकार को यदि अलविदा कर दिया जाए तो सारी ऊर्जा हमारे स्वयं के सृजन के लिए उपलब्ध रहेगी जिससे सृजन की गुणवत्ता में भी आशातीत परिवर्तन होता रहेगा। इस स्थिति में व्यक्तित्व निश्चित ही बढ़ेगा। अपने में इस प्रकार का सृजन करके हम उस विराट को स्वयं में रहने देने के लिए मार्ग बना देते हैं, लेकिन ऐसा तभी तक संभव है जब तक अहंकार नहीं लौटता है।

मानव की सदैव से यही कमी रही है कि वह कभी भी मौन नहीं रह पाता है। बिना शोर के वह रह ही नहीं पाता। ऐसे में जो होता है वह बहुत ही अशांत और उपद्रव से भरा होता है। कोई भी सृजनात्मक कार्य चाहे वह लेखन में हो, चित्रकला में हो या किसी अन्य तरह के सृजन में हो, इसमें जब अहंकार आ जाता है तब यही सृजन भारी शोर के साथ लोगों को बताता है कि मैंने यह उत्तम कार्य किया है, लेकिन सचमुच का सृजन और सौंदर्य तभी प्रकट होता है जब हम परमात्मा के प्रति गहन अनुग्रह और श्रद्धा के भावों से भरे होकर एकदम शांत और मौन होते हैं।

वीके जायसवाल

घाटी में पर्यटन उद्योग

8 जुलाई, 2016 को जब आतंकी बुरहान वानी को सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में मार गिराया था उस वक्त मैं श्रीनगर में था और हफ्ते भर पहले अमरनाथ यात्रा शुरू हुई थी। मैंने अमरनाथ गुफा तक की यात्रा बालटाल और पहलगाम दोनों रास्तों से की थी और तब घाटी के विभिन्न इलाकों में रिपोर्टिंग के वास्ते घूमा भी था। उस साल ईद 6 या 7 तारीख की हुई थी और मैं कश्मीरी सिवइयों का स्वाद लेने डल झील के पास के बाजार में घूम रहा था और वहीं एक भिखारी कुछ मांगने आ गया। कश्मीरी पंडित मूल की एक साथी पत्रकार ने तब मुझे बताया था कि कश्मीरी लोग भीख नहीं मांगते और बाहरी लोग आकर कश्मीर की समृद्ध फिजां में भीख मांगने की रवायत शुरू कर रहे हैं।

वैसे मैंने कश्मीर घाटी में कहीं मकान झोपड़ीनुमा नहीं देखे। हर जगह मकान बढ़िया बने थे, जबकि इसकी तुलना में उत्तर भारतीय राज्यों का लैंडस्केप ज्यादा टेढ़ा-मेढ़ा है, गुरबत और धूल-धक्कड़ से भरा है। तब से यह सवाल मेरे जेहन में लगातार घूम रहा था कि क्या वाकई कश्मीरी लोग भीख नहीं मांगते? और अगर उस पत्रकार की बात सच थी तो क्यों नहीं मांगते? जबकि सरकारी आंकड़े कश्मीर की आर्थिक

फिर से

प्रश्न है कि क्या बेहतर आर्थिक विकास कश्मीर के युवाओं में बढ़ते अलगाव को थामने में कामयाब होगा?

स्थिति के बारे में कुछ और ही खुलासा कर रहे हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि कश्मीर में 2014 के बाद से आतंकवाद में इजाफा हुआ है। सिर्फ 2018 की बात करें तो कश्मीर घाटी में 614 आतंकी घटनाएं हुई हैं, जबकि 2014 में 222 हुई थीं। 2018 में 257 आतंकवादी मारे गए हैं और 2014 में 110 आतंकवादी ढेर किए गए थे। इसी तरह पाकिस्तान ने भी घाटी में अपनी गतिविधियां तेज की हैं। 2016 से 2018 के बीच 398 आतंकियों ने कश्मीर में घुसपैठ की।

वैसे कश्मीर में बेरोजगारी की दर भी बाकी देश के औसत से कहीं अधिक है। कश्मीर में 18 से 29 साल के आयु वर्ग में बेरोजगारी की दर 24.6 फीसद है, जबकि राष्ट्रीय औसत 13.2 फीसद है। जुलाई 2016 से जून 2017 के बीच 130 कार्यदिवसों का नुकसान घाटी में हड़ताल और कर्फ्यू से हुआ था। इसकी अनुमानित लागत 13,261 करोड़ रुपये आंकी गई है। जहां तक विकास दर की बात है तो राज्य में वित्त वर्ष 2017-18 में 8.2 फीसद की विकास दर दर्ज की गई थी। 2019 में जम्मू-कश्मीर का राज्य जीडीपी करीब 25 अरब डॉलर का है और देश के तमाम राज्यों के लिहाज से विकास की सीढ़ी पर वह 21वें पायदान पर है। प्रदेश में पर्यटन भी गोते लगा रहा है। साल 2018 में कश्मीर में 8.5 लाख देसी और विदेशी सैलानी आए थे। 2017 की तुलना में यह 23 फीसद कम है।

दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर घाटी में आए बाढ़ के बाद राहत एवं ढांचागत विकास, स्वास्थ्य कल्याण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 80,000 करोड़ रुपये का पैकेज दिया था। फिर भी इन आंकड़ों से एक बात साफ होती है कि कश्मीर की आर्थिक हालत खराब ही है। सवाल है कि क्या बेहतर आर्थिक विकास कश्मीर के नौजवानों में बढ़ते अलगाव को थामने में कामयाब होगा? मेरा मानना है कि आर्थिक गतिविधियों के साथ ही खुले मन से बातचीत के कदम भी बढ़ाए जाने चाहिए।

(साभार : गुस्ताख ब्लॉग में मंजित ठाकुर)

मेलबाक्स

जनता तय करेगी किस्मत

प्रदीप सिंह ने अपने आलेख 'रणनीति बदलने को विवश विपक्ष' के माध्यम से लोकसभा चुनाव में जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से पार्टियों के बीच हो रहे घमासान पर प्रकाश डाला है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां सरकार का चुनाव देश की जनता के वोटों के आधार पर होता है। जनता उस पार्टी को सरकार में लाना चाहती है, जिसने जनता का विश्वास जीता हो। जिस पर जनता आश्वस्त हो सके कि वह पार्टी सरकार में आने के उपरांत देश में व्याप्त समस्याओं को दूर कर सकने में सक्षम होगी। जब कोई भी पार्टी सरकार में आने के बाद देशहित के लिए कार्य करती है तो उसके सकारात्मक असर धीरे-धीरे दिखने लगते हैं। हालांकि जब देश में ऐसी समस्याएं लंबे समय से व्याप्त हों, जो देश के विकास के प्रतिकूल हों तो जनता को उससे निजात दिलाने में लंबा वक्त लग सकता है, इसलिए सब्र रखना अत्यंत आवश्यक है। पांच वर्षों की बेहद छोटी-सी अवधि में किसी भी सरकार द्वारा देशहित में किए गए कार्यों का सही से आकलन कर पाना मुश्किल हो सकता है। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में लाजिमी है कि हर पार्टी सत्तारूढ़ होने के उद्देश्य से एक-दूसरे पर आरोप लगाकर जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहेगी, परंतु देश की जनता इतनी जागरूक है कि वह उस पार्टी को ही चुनेगी, जिसको वह देश के विकास के लिए काबिल समझेगी। अब पार्टियों की किस्मत देश की जनता तय करेगी।

सौरभ पाठक, ग्रेटर नोएडा

कानून सम्मत राष्ट्रभाव की जरूरत

यह एक तथ्य है कि जब-जब इस देश में युद्ध जैसी परिस्थितियां बनती हैं तो राष्ट्रभाव का ऐसा आलोड़न उठता है कि भारत का जन-जन उसमें डूबता दिखाई देता है। लेकिन फिर भी कुछ स्वार्थी तत्व अपने दुष्कृत्य से देश के दुश्मनों को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। विवेक काटजू अपने आलेख दबाव से उबरने न पाए पाकिस्तान में शायद इस तथ्य को उल्लिखित करना भूल गए कि पिछले तीन दशकों से पाकिस्तान आतंकवाद के जरिये भारत के विरुद्ध जैसा युद्ध सरीखा छद्म युद्ध छेड़े हुए है, उसे पोषित करने वाली इस देश की वह वोटखोर राजनीति ही है जो आज सत्ता की भूख में अंधी हो चुकी है। देश की इस राजनीतिक विकृति का फायदा अपनी भारत विरोधी वैचारिकी को प्रसारित करने वाले वे लोग भी उठा रहे हैं जो यह नहीं चाहते कि भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में विकसित हो। ऐसे में भारत जैसे समक्ष राष्ट्र को लोकतांत्रिक दायरे को तोड़े बिना देश के अंदर विकृत राजनीति पर लगाम लगाने की जरूरत है। जाहिर है यह काम आसान नहीं है, इसके लिए एक कठोर राष्ट्रीय नागरिक आचार संहिता बनाने की जरूरत है जो संवैधानिक कानून की तरह प्रभावी होकर इसका उल्लंघन करने वाले हर व्यक्ति को दंडित करने का काम करे। यद्यपि भारतीय संविधान में राष्ट्रद्रोह का कानून मौजूद है, लेकिन इस लचर कानून को भारत में पल रहे टुकड़े-टुकड़े गैंग के सदस्य अभिव्यक्ति की आजादी की ओट में किस तरह से हवा में उड़ा रहे हैं, यह किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में जब तक भारत के अंदर कानून सम्मत राष्ट्रभाव विकसित नहीं होगा तब तक पाकिस्तान जैसे बेहद झूठे, मक्कार और फरेबी देश पर दबाव बनाना मुश्किल है।

डॉ. वीपी पाण्डेय, एसोसिएट प्रोफेसर, अलीगढ़

विपक्ष को सुनने के लिए तैयार नहीं जनता!

रणनीति बदलने को विवश विपक्ष शीर्षक से प्रकाशित प्रदीप सिंह का आलेख विपक्ष के सत्ता पक्ष को नीचा दिखाने के लिए बनाई गई नीतियों का लाचर परिदृश्य प्रस्तुत कर रहा है। कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों ने मिलकर मोदी सरकार को प्रत्येक मोर्चे पर घेरने की पूरी कोशिश की, यहां तक कि सपा-बसपा का गठबंधन हुआ, कांग्रेस में प्रियंका गांधी की बहुप्रतीक्षित एंट्री भी हुई। लेकिन मोदी सरकार के 4 साल तो दूर पांचवें साल के अंतिम दिनों में पाक प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ की गई कार्रवाई के सामने हर रणनीति फीकी पड़ चुकी है। मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था से लेकर देश की सुरक्षा, किसान से लेकर कर्मचारी तक कमोबेश हर वर्ग को खुश करने की पूरी कोशिश की है। प्रधानमंत्री मोदी के पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने के बाद और वायु सेना द्वारा एयर स्ट्राइक के दस्तावेज पेश करने के बाद विपक्ष के पास जनता को बरगलाने के लिए सिर्फ बातें बची हैं, कोई मुद्दा नहीं। वैसे भी देश के वर्तमान हालात में जनता विपक्ष को सुनने के लिए तैयार नहीं है।

पिंटू सक्सेना, लखनऊ

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।